

मुकदमों का विवरण

रामथल और ओआरएस. वी.

विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)। AND ANDRI (2012 की सिविल अपील सं. 8830)

अगस्त 17,2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय का यह विचार कि विचारण न्यायालय के समक्ष न तो कोई अभिवचन था और न ही गैर-वास्तविक याचिका के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था और इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के पक्ष में उक्त याचिका का निर्धारण करने में त्रुटि की-परिणामस्वरूप, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

मुकदमा-वादी ने मुकदमे की संपत्तियों के पूर्ण मालिकों के रूप में घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया और इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए भी कि अटॉर्नी की सामान्य शक्ति में गलत प्रतिनिधित्व था-निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया-पहली अपीलीय अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया-उच्च न्यायालय ने एक आदेश दर्ज करने के लिए आगे बढ़कर कहा कि गैर-वास्तविक याचिका के संबंध में न तो कोई याचिका दायर की गई थी और न ही कोई मुद्दा तैयार किया गया था और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दायर अपील:

आयोजित किया गया: वाद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने का उद्देश्य केवल विचाराधीन संपत्ति को छोटे भूखंडों में विकसित करना और संबंधित अधिकारियों से उसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना था-वाद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वादी अनपढ़ थे और उनके पास उपरोक्त अभ्यास करने का कोई साधन नहीं था और चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी अधिकारियों के साथ व्यवहार करने में अच्छी तरह से पारंगत था, इसलिए वह भूखंडों को विकसित करने में उनकी मदद कर सकता था-वाद तब शुरू किया गया था जब वादी को एहसास हुआ कि प्रतिवादी के पास दो अतिरिक्त खंड थे जो उसे बेचने, उपहार देने, विचाराधीन भूखंडों का निपटान करने और जहां भी आवश्यक हो पट्टा के हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते थे।

348 349

रामथल और ओआरएस. वी. विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI

कार्य-वादी का कभी भी एक ही उद्देश्य नहीं था-विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए मुद्दे (i) क्या वादी वाद संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं और (ii) क्या वादी के कब्जे में हैं और वाद संपत्ति का आनंद लेना गैर-तथ्य के मुद्दे को शामिल करेगा-वाद के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि गैर-तथ्य की याचिका को स्पष्ट और सख्त शब्दों में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी दोनों, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना और विश्लेषण किया था, ताकि इस तथ्य को दर्ज किया जा सके कि गैर-तथ्य की याचिका साबित हुई थी-उच्च न्यायालय का निर्णय दरकिनार कर दिया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे बनाए रखा।[पारस 16,25,26 से 29]

मैक्सिम-गैर तथ्य-कब याचिका ली जा सकती है:

आयोजित किया गया:विलेख के निष्पादक या हस्ताक्षरकर्ता द्वारा गैर-तथ्य की याचिका यह दलील देने के लिए ली जा सकती है कि उक्त दस्तावेज़ अमान्य है क्योंकि इसके निष्पादक/हस्ताक्षरकर्ता को निष्पादित/हस्ताक्षर करने के समय इसके चरित्र के बारे में गलत समझा गया था-यह एक लैटिन उक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है "यह विलेख नहीं है"-गैर-तथ्य की याचिका अनुबंध कानून में उपलब्ध एक बचाव है जो एक व्यक्ति को उस दस्तावेज़ के प्रभाव से बचने की अनुमति देती है जिसे उसने निष्पादित/हस्ताक्षर किया हो सकता है।[पैरा 17]

मैक्सिम-नॉन एस्ट फैक्टम-नॉन एस्ट फैक्टम की सफल दलील के लिए आवश्यक है:

आयोजित किया गया:(i) गैर-तथ्य का अनुरोध करने वाला व्यक्ति "उन व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जो अपनी गलती के बिना, अंधेपन, निरक्षरता या किसी अन्य अक्षमता के कारण विशेष दस्तावेज़ के उद्देश्य की कोई समझ रखने में असमर्थ हैं"-अक्षमता वह होनी चाहिए जिसमें सलाह के लिए दूसरों पर निर्भरता की आवश्यकता हो कि वे क्या हस्ताक्षर कर रहे हैं; (ii) "हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए जा रहे दस्तावेज़ की सामग्री की प्रकृति के बारे में एक मौलिक गलती की होगी", जिसमें इसके व्यावहारिक प्रभाव भी शामिल हैं; (iii) दस्तावेज़ हस्ताक्षर किए जाने के इरादे से मौलिक रूप से अलग होना चाहिए।[पैरा 19]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

श्रीमती. बिस्मिल्लाह बनाम जनेश्वर प्रसाद और अन्य (1990) 1 एससीसी 207;

भगवती प्रसाद बनाम चंद्रमौल ए. आई. आर 1966 एस. सी. 735:[1966] एससीआर 286;

बछाज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और एक अन्य (2008) 17 एस. सी. सी. 491-आश्रित पर।

श्री सिन्हा रामनुजा जीर और अन्य बनाम श्री रंगा रामानुजा जीर और एक अन्य (1962) 2 एससीआर 509; रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य

350 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(2019) 17 एससीसी 71; प्रेम सिंह और अन्य बनाम बीरबल और ओआरएस। 2006 (5) एससीसी 353:[2006] 1 पूरकाएस. सी. आर. 692; पेंटाकोटा सत्यनारायण बनाम पेंटाकोटा

सीतारत्नम 2005 (8) एस. सी. सी. 67:[2005] 3 पूरकाएससीआर 719; आईटीसी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 2011 (7) एससीसी 493:[2011] 7 एससीआर 66; एम. एम. एस.

निवेश, मदुरै और अन्य। बनाम वी. वीरप्पन और अन्य। 2007 (9) एससीसी 660: [2007] 5 एससीआर 32; आई. एस. सिकंदर (मृत) एल. आर. बनाम के. सुब्रमण्यन और अन्य।

2013 (15) एससीसी 27:[2013] 17 एस. सी. आर. 24; सी. चंद्रमोहन बनाम सेनगोट्टेयन (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। 2000 (1) एससीसी 451:[2000] 1 एस. सी. आर. 16; कावेरी कॉफ़ ई

ट्रेडर्स, मैंगलोर बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड

2011 (10) एससीसी 420:[2011] 12 एससीआर 473; ताहेराखातून (डी) एल. आर. बनाम.सलामबीन मोहम्मद 1999 (2) एस. सी. सी. 635:[1999] 1 एस. सी. आर. 901; निंगावा बनाम बैरप्पा ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 956:[1968] एस. सी. आर. 797-संदर्भित।

सॉन्डर्स बनाम एंग्लिया बिल्डिंग सोसाइटी (1970) 3 ऑल ई. आर. 961-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील सं. 8830।2002 के एस. ए. सं. 648 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2008 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

जयंत मुथ राज, वरिष्ठ अधिवक्ता, निशे राजन शोंकर, श्रीमती मालविका जयंत, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।

के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, राजीव गुप्ता, विनय राजपूत, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. वादी की वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश की शुद्धता पर हमला करती है, जिसके तहत 2002 की दूसरी अपील संख्या 648 का शीर्षक है

"N.Krishnasamy मुदलियार (D) और अन्य। बनाम रामथल और अन्य। "351 था।

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 352

अनुमति दी गई, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने के बाद, विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया गया, और वादी (वर्तमान अपीलार्थी) के मुकदमे को खारिज कर दिया गया।

2. विवाद संख्या 95, पूर्वी अयाकुडी गाँव, पलानी, तमिलनाडु में 110 सेंट भूमि से संबंधित है जो मूल रूप से प्रथम वादी, नचीमुथु की थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी रामथल के पक्ष में 50 सेंट भूमि के संबंध में एक उपहार विलेख निष्पादित किया था। मुकदमे का नेतृत्व संयुक्त रूप से नचीमुथु और उनकी पत्नी रामथल ने किया था, जिन्हें वादी एन. ओ. एस. के रूप में वर्णित किया गया था। क्रमशः 1 और 2।

3. उसी गाँव अयाकुडी में, एक कृष्णसामी और उनके दो बेटे, राजामणि और शक्तिवेलु भी रह रहे थे और वादी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। अशिक्षित होने और आय का कोई अन्य स्रोत न होने के कारण, वादी ने राजामणि से सरकारी अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद भूमि को कई भूखंडों में विकसित करने का अनुरोध किया ताकि वादी के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए उक्त भूखंडों को बेचा जा सके। इस सेवा के बदले में, उन्होंने राजामणि को पांच सेंट जमीन दी। 4. वादी द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के लिए राजमणि के पक्ष में दिनांकित एक पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया गया था। उक्त विलेख को पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष 17.09.1986 पर प्रस्तुत किया गया था और 19.09.1986 पर पंजीकृत किया गया था। वादी के अनुसार, राजामणि ने उनकी निरक्षरता और सादगी का लाभ उठाते हुए, उस उद्देश्य के अलावा, जिसके लिए वादी ने पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने का अनुरोध किया था, इसमें दो और खंड जोड़े। सबसे पहले, वकील को संपत्ति बेचने का अधिकार होगा, और दूसरा, पट्टा हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में समर्थन करने का अधिकार होगा।

5. उस तारीख को, पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत किया गया था अर्थात् 19.09.1986, राजामणि ने दो बिक्री विलेख निष्पादित किए: एक अपने पिता कृष्णसामी के पक्ष में 50 सेंट भूमि के लिए और दूसरा अपने छोटे भाई शक्तिवेलु के पक्ष में 50 सेंट भूमि के लिए। दोनों बिक्री विलेखों का कम मूल्यांकन किया गया था, क्योंकि बिक्री पर विचार रु। 6, 000/- प्रति बिक्री विलेख और उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था। हालाँकि, संपत्ति के दिशानिर्देश मूल्य के अनुसार, पहली बिक्री का मूल्य रु। 15, 000/- और दूसरी बिक्री रु। 7,

500/-। कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क की अवहेलना को देखते हुए, दोनों दस्तावेजों को अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। 6. 1988 में किसी समय, कृष्णसामी और उनके दो बेटों, राजमणि और शक्तिवेलु ने सूट में भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

तभी वादी को राजामणि द्वारा अपने पिता और भाई के पक्ष में किए गए दो बिक्री विलेखों के बारे में पता चला। उन्होंने वादी को उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की धमकी भी दी। आई. डी. 1 पर, वादी ने पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की, और उसके तुरंत बाद, वादी को राजमणि द्वारा बेचने, बंधक बनाने, बिक्री विलेख निष्पादित करने, निपटान विलेख, उपहार विलेख, विनिमय विलेख और पट्टा हस्तांतरण के लिए समर्थन करने और यदि आवश्यक हो, तो संबंधित प्राधिकरण से लेआउट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वाद संपत्ति को भूखंडों में विभाजित करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए की गई शरारत के बारे में पता चला।

7. इस प्रकार वादी कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने 29.04.1991 पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस जारी किया, जो दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। अक्टूबर 1991 में, वादी ने मुकदमे की संपत्तियों के पूर्ण मालिकों के रूप में घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया और इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए भी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में गलत प्रस्तुति थी। यह पलानी में जिला मुन्सिफ के न्यायालय में 1991 के मूल मुकदमा संख्या 839 के रूप में पंजीकृत किया गया था। पिता कृष्णसामी को प्रतिवादी नं. 1, राजामणि, वकील, को प्रतिवादी सं. 2 और शक्तिवेलु को प्रतिवादी सं. 3. प्रतिवादी एन. ओ. एस 1 और 2 ने केवल अपने लिखित बयान दिए जबकि प्रतिवादी नं. 3 ने मुकदमे का विरोध नहीं करने का फैसला किया, और उनकी ओर से कोई लिखित बयान नहीं दिया गया।

8. दोनों पक्षों ने दस्तावेजी और मौखिक दोनों तरह के साक्ष्य दिए। ट्रायल कोर्ट ने 06.01.1998 के फैसले और आदेश के माध्यम से, पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री के वास्तविक होने पर भरोसा करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। इसने वादी की याचिका को स्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी नं. 2 ने बेचने की शक्ति और पट्टा आदि के हस्तांतरण के अन्य खंडों को शामिल करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया और शरारत की, जिसे वादी के अनुसार उन्होंने कभी अधिकृत नहीं किया था।

9. वादी ने पलानी में उप-अदालत के समक्ष पहली अपील की जिसे 1998 के ए. एस. संख्या 28 के रूप में पंजीकृत किया गया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रथम वादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में लाया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गैर-वास्तविक तथ्य के बिंदु सहित विचार के लिए बिंदु तैयार किए और मौखिक

और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों के उचित विश्लेषण और मूल्यांकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री को धोखाधड़ी से बिना किसी देय के शामिल किया गया था।

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 354

केवल वादी को उनके मूल्यवान अधिकारों से वंचित करने के लिए प्राधिकरण।अपील को स्वीकार कर लिया गया और मुकदमे का फैसला सुनाया गया।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दर्ज किए:

((i))।पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण के दिन अटॉर्नी द्वारा निष्पादित दो बिक्री विलेखों की सामग्री प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्रासंगिक तथ्य है और उनके आचरण को दुर्भावनापूर्ण दर्शाती है।

((ख))।बिक्री विलेख का कम मूल्यांकन किया गया था और यह बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता था।यहां तक कि दिशानिर्देश मूल्य को भी वापस नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप बिक्री विलेख जब्त कर लिए गए थे।

((iii))।अवज्ञाकारी स्टाम्प शुल्क का भुगतान 1995 और 1997 में बिक्री विलेखों को नियमित करने और जारी करने के लिए किया गया था, जो इसके निष्पादन की तारीख से क्रमशः नौ और ग्यारह साल बाद था।यह भी 1991 में वादी द्वारा वाद की स्थापना की तुलना में बहुत बाद में था।

((iv))।बिक्री विलेखों में प्रतिफलित बिक्री प्रतिफल भी दिशानिर्देश मूल्य से बहुत कम था, और भले ही इसका भुगतान वादी को किया गया हो, यह वाद में भूमि के लिए एक उचित प्रतिफल नहीं था।

(वी)।प्रतिवादियों ने अपनी निरक्षरता और साधनशीलता का अनुचित लाभ उठाते हुए वादी को उनकी मूल्यवान भूमि से वंचित कर दिया था, क्योंकि वे अनपढ़ और साधारण देहाती ग्रामीण थे।

(vi)।प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज दीवानी मुकदमे की स्थापना के बाद की अवधि के थे।

(vii)।मूल पावर ऑफ अटॉर्नी को कभी पेश नहीं किया गया था, और यह आरोप लगाया गया था कि वह खो गया था।

(viii)।प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहे कि वादी ने जानबूझकर और स्वेच्छा से, पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री को समझने के बाद, इसे निष्पादित किया था।

(ix)।गैर-तथ्य का सिद्धांत वादी के पक्ष में तय किया गया था।

10. प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांक 13.02.2002 उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में लिया गया था और 2002 की दूसरी अपील No.648 के रूप में दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने तय किया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कानून का निम्नलिखित प्रश्न: “चाहे प्रथम अपीलीय न्यायालय, किसी भी मुद्दे के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा या स्वयं द्वारा तैयार किया गया हो और पूर्व से संबंधित गैर-तथ्य की याचिका के संबंध में प्रासंगिक अभिवचनों के अभाव में भी। ए 1, को वादी एस के पक्ष में निर्णय देने में उचित ठहराया गया था?” और प्रतिवादियों के पक्ष में भी यही फैसला किया।

11. उच्च न्यायालय का विचार था कि विचारण न्यायालय के समक्ष न तो कोई अभिवचन था और न ही गैर-वास्तविक याचिका के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था और इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी के पक्ष में उक्त याचिका का निर्धारण करने में त्रुटि की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से, तदनुसार अपील की अनुमति दी, और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने के बाद, निचली अदालत के आदेश को बहाल किया और मुकदमे को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, वर्तमान अपील वादी द्वारा की गई है।

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

13. अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

((i))।वादी का मामला शुरू से ही इस आशय का था कि उन्होंने केवल छोटे भूखंडों में विभाजित करके और अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके भूमि के विकास के सीमित उद्देश्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन किया था।

((ख))।उन्होंने कभी भी प्रतिवादी नं. को अधिकृत करने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित नहीं किया था। 2. बेचना, बंधक बनाना, उपहार विलेख निष्पादित करना, विवादग्रस्त भूमि का निपटारा करना या पट्टा अनुदान के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करना। प्रतिवादी नं. द्वारा इस तरह के खंडों को शरारतपूर्ण और गुप्त रूप से जोड़ा गया था। 2 वादी की सरलता और निरक्षरता का अनुचित लाभ उठाना।

((iii))।वादी ने कभी भी विवादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपा और पूरे समय उसी पर कब्जा बनाए रखा। ((iv))।वकील का आचरण, प्रतिवादी सं। 2, जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी

पंजीकृत किया गया था, उसी दिन अपने पिता और भाई को भूमि हस्तांतरित करने से पता चलता है कि अटॉर्नी की ओर से द्वेष था। प्रतिवादी नं. 2 स्पष्ट रूप से 355 था

रामथल और ओआरएस. वी. विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 356

आशंका है कि यदि वादी को पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री के बारे में पता चला है, जो प्रतिवादी सं. 2 जमीन बेचने के लिए, उन्होंने इसे रद्द कर दिया होगा। इसलिए, बिना कोई जोखिम उठाए क्योंकि कोई भी देरी उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे को विफल कर देगी, उसने अपने पिता और भाई के पक्ष में मामूली राशि के लिए बिक्री विलेख को निष्पादित किया।

(वी)। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गैर-तथ्य की याचिका को विचार के बिंदुओं में से एक के रूप में उचित रूप से निर्धारित किया था, जो अभिवचनों पर आधारित था और इसके लिए किसी विशिष्ट मुद्दे को तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसे पहले से तैयार किए गए मुद्दों के हिस्से के रूप में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा।

(vi)। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि कोई अभिवचन नहीं था, जो अभिलेख के विपरीत है।

(vii)। अपीलार्थी की दलीलों के समर्थन में उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया है:

क) श्रीमती। बिस्मिल्लाह बनाम जनेश्वर प्रसाद और अन्य **1, ख)** श्री सिन्ना रामनुजा जीर और अन्य बनाम श्री रंगा रामनुजा जीर और अन्य **2,**

ग) रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य **3.**

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

((i)। वादी एस, पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन को स्वीकार करने के बाद, इसकी सामग्री को विवादित नहीं किया जा सकता था।

((ख)। वादी ने यह दलील देते हुए कि उन्होंने 1988 में पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने या बिक्री विलेख को रद्द करने या किसी भी आपराधिक कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, और लगभग तीन साल बाद ही मुकदमा वर्ष 1991 में शुरू किया गया था।

((iii)। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को उलट नहीं दिया कि रुपये की बिक्री पर विचार किया जाए। 12, 000/- का भुगतान किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वादी एस।कब्जा करने का निर्णय प्रतिवादियों के पक्ष में था, क्योंकि वादी ने अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, जबकि प्रतिवादियों के पास अपने कब्जे को स्थापित करने के लिए दस्तावेज (डी-03 से डी-14) थे।(iv)।वादी ने गलत दलील दी थी कि वे अनपढ़ थे, जबकि वास्तव में उच्च न्यायालय ने यह तथ्य दर्ज किया था कि वे साक्षर हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने में उनके भाइयों और चचेरे भाइयों द्वारा उनकी कुशलता से सहायता की गई थी।वादी ने प्रतिवादियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का अनुरोध नहीं किया।

(वी)।पावर ऑफ अटॉर्नी एक पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण, इसकी सामग्री को तब तक सही माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री की शुद्धता का अनुमान है।

(vi)।मुकदमा विचारणीय नहीं था क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी को दरकिनार करने या बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

(vii)।वादी द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन को स्वीकार करने के मद्देनजर गैर-तथ्य के सिद्धांत का अनुप्रयोग उत्पन्न नहीं होगा।

(viii)।बिक्री आय प्राप्त करने और प्रतिवादियों को कब्जा सौंपने के बाद वादी पलट नहीं सकता है और इसके विपरीत रुख नहीं अपना सकता है।

(ix)।इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील का दायरा बहुत सीमित है, और जब तक असाधारण और विशेष परिस्थितियों को उच्च न्यायालय के फैसले में विकृति स्थापित करने के लिए नहीं दिखाया जाता है, तब तक किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

(x)।रिलायंस को उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया है:

क) प्रेम सिंह और अन्य बनाम बीरबल और ओआरएस। **4,**

ख) पेंटाकोटा सत्यनारायण बनाम पेंटाकोटा सीतारत्नम **5,**

4 2006 (5) एससीसी 353 5 2005 (8) एससीसी 67 357

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 358

ग) आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 6,घ) एम. एम. एस. निवेश, मदुरै और अन्य। बनाम। वी. वीरप्पन और अन्य। 7,

ई) आई. एस. सिकंदर (मृत) एल. आर. बनाम। के. सुब्रमण्यन और अन्य। 8,च) सी. चंद्रमोहन बनाम सेनगोठैयन (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। 9,

छ) कावेरी कॉफी ट्रेडर्स, मैंगलोर बनाम हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड 10,

ज) ताहेराखातून (डी) बनाम एल. आर.सलामबीन मोहम्मद 11

15. चूंकि उच्च न्यायालय ने एक आदेश दर्ज करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया कि न तो कोई अभिवचन था और न ही गैर-तथ्य की याचिका के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था, इसलिए शिकायत की सामग्री के साथ पहले निपटना उचित होगा।

16. वाद के पैराग्राफ नंबर 6 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित करने का उद्देश्य केवल विचाराधीन संपत्ति को छोटे भूखंडों में विकसित करना और संबंधित अधिकारियों से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना था। वाद के पैराग्राफ 10 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वादी अनपढ़ थे और उनके पास उपरोक्त अभ्यास करने का कोई साधन नहीं था और चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी प्राधिकरणों के साथ व्यवहार करने में अच्छी तरह से पारंगत था, इसलिए वह भूखंडों को विकसित करने में उनकी मदद कर सकता था। इसके अलावा, पैराग्राफ 10 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1991 में दस्तावेजों को पढ़ने के बाद, वादी को एहसास हुआ कि प्रतिवादी के पास दो अतिरिक्त खंड शामिल थे जो उसे बेचने, उपहार देने, विचाराधीन भूखंडों का निपटान करने और पट्टा विलेखों के जहां भी आवश्यक हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते थे। ऐसा इरादा कभी नहीं था। पावर ऑफ अटॉर्नी डीड में दर्ज इन दो अतिरिक्त अधिकारों का न तो इरादा था और न ही उन्हें सूचित किया गया था। वादपत्र में यह भी कहा गया है कि वादी की निरक्षरता और सादगी का लाभ उठाते हुए, ऐसे अधिकारों को पावर ऑफ अटॉर्नी में शामिल किया गया है।

6 2011 (7) एससीसी 493 7 2007 (9) एससीसी 660 8 2013 (15) एससीसी 27 9 2000 (1) एससीसी 451 10 2011 (10) एससीसी 420 11 1999 (2) एससीसी 635

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

17. विलेख के निष्पादक या हस्ताक्षरकर्ता द्वारा गैर-तथ्य की याचिका यह दलील देने के लिए ली जा सकती है कि उक्त दस्तावेज अमान्य है क्योंकि इसके निष्पादक/हस्ताक्षरकर्ता को निष्पादित/हस्ताक्षर करने के समय इसके चरित्र के बारे में गलत समझा गया था। यह एक लैटिन उक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है "यह विलेख नहीं है।" तथ्यहीन याचिका अनुबंध

कानून में उपलब्ध एक बचाव है जो किसी व्यक्ति को उस दस्तावेज़ के प्रभाव से बचने की अनुमति देता है जिसे उसने निष्पादित/हस्ताक्षरित किया हो सकता है।

18. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, गैर-तथ्य की दलील का मूल रूप से अर्थ है, "यह मेरा कार्य नहीं है।" उक्त याचिका विचार का विषय रही है।

बिस्मिल्लाह बनाम जनेश्वर प्रसाद (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का।में।

उक्त मामले में, वादी/अपीलार्थी ने खुद को एक परदनाशीन महिला होने का दावा किया था और प्रतिवादी/प्रत्यर्थियों के प्रतिनिधित्व पर, उन्हें एक लिखित दस्तावेज़ के तहत संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, जिसका मसौदा हिंदी में तैयार किया गया था, एक ऐसी भाषा जो उसे ज्ञात नहीं थी।बाद में, उन्हें पता चला कि इसमें संपत्तियों की बिक्री को सशक्त बनाने वाला एक अनधिकृत खंड है।उसी का लाभ उठाते हुए, उक्त एजेंटों ने उक्त संपत्ति की धोखाधड़ी और मायावी बिक्री को अंजाम दिया था।वादी/अपीलार्थी द्वारा स्थापित उक्त मामले पर विचार किया गया और रिपोर्ट के पैरा 12 और 13 में निपटा गया। एक और मुद्दा जिस पर इस न्यायालय ने उक्त मामले में विचार किया, वह दस्तावेज़ के चरित्र के रूप में धोखाधड़ी से गलत प्रतिनिधित्व और उसकी सामग्री के रूप में धोखाधड़ी से गलत प्रतिनिधित्व के बीच का अंतर था।गैर-तथ्य का ऐसा बचाव केवल वहीं उपलब्ध माना जाता था जहां लेन-देन की प्रकृति या चरित्र के बारे में गलती थी।इस न्यायालय ने निंगावा बनाम बैरप्पा 12 के मामले में पहले के एक निर्णय पर भी भरोसा किया।इस न्यायालय ने आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर भरोसा रखा

सॉन्डर्स बनाम एंग्लिया बिल्डिंग सोसाइटी **13** का मामला अंतर को ठीक करने के लिए

दस्तावेज़ के शून्य या शून्य होने के बीच।बिस्मिल्लाह (ऊपर) के अनुच्छेद **11** से **15** को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“11. उच्च न्यायालय के तर्क में अंतर्निहित धारणा यह है कि यदि कार्रवाई वास्तव में विलेखों को रद्द करने की आवश्यकता पर आधारित होती, जिसके बिना कब्जा नहीं दिया जा सकता था, तो दीवानी अदालत के पास अधिकार क्षेत्र होता।अपीलार्थी के मुकदमे में कार्रवाई का कारण मामलों के इस वर्ग के भीतर लाए जाने को स्वीकार करता है।

12 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 956

13 (1970) 3 सभी ईआर 961 359

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 360

12. इसके मूल में विशिष्टताओं पर कार्रवाई के लिए गैर-तथ्य का सामान्य कानून बचाव उपलब्ध था, जहां एक अनपढ़ व्यक्ति, जिसे किसी विलेख की सामग्री गलत तरीके से पढ़ी गई

थी, ने इसकी प्रकृति और सामग्री के बारे में गलती से इसे निष्पादित किया, वह कह सकता था कि यह उसका विलेख बिल्कुल नहीं था। अपने आधुनिक अनुप्रयोग में, इस सिद्धांत को निरक्षरता के अलावा अन्य मामलों और लिखित रूप में अन्य अनुबंधों तक विस्तारित किया गया है। जिन अधिकांश मामलों में इस बचाव का अनुरोध किया गया था, उनमें गलती धोखाधड़ी से प्रेरित थी; लेकिन यह शायद एक आवश्यक कारक नहीं था, क्योंकि लेन-देन "न केवल धोखाधड़ी के आधार पर अमान्य है, जहां धोखाधड़ी मौजूद है, बल्कि इस आधार पर कि हस्ताक्षरकर्ता का दिमाग हस्ताक्षर के साथ नहीं था; दूसरे शब्दों में, कि वह कभी भी हस्ताक्षर करने का इरादा नहीं रखता था, और इसलिए, कानून के विचार में कभी भी उस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिसमें उसका नाम जोड़ा गया है"।

13. अधिकारियों ने दस्तावेज़ के चरित्र के रूप में धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण और उसकी सामग्री के रूप में धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के बीच अंतर किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बचाव केवल तभी उपलब्ध था जब गलती लेन-देन की प्रकृति या चरित्र के बारे में थी।

14. फोस्टर बनाम मैकिनन [(1869) एलआर 4 सीपी 704:38 एल. जे. सी. पी. 310], मैकिनन, प्रतिवादी को इस झूठे अभ्यावेदन पर विनिमय विधेयक का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया गया था कि यह उसी तरह की गारंटी थी जिस पर उसने पिछले अवसर पर हस्ताक्षर किए थे। विधेयक के एक निर्दोष समर्थक द्वारा मुकदमा किए जाने पर भी उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। जे. बाइल्स ने कहा:

"..... प्रतिवादी का उस अनुबंध या ऐसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का इरादा कभी नहीं था। उनका इरादा कभी भी किसी ऐसे दस्तावेज़ में अपना नाम डालने का नहीं था जो तब या उसके बाद बातचीत के योग्य हो। उन्हें धोखा दिया गया, न केवल कानूनी प्रभाव के बारे में, बल्कि उपकरण की 'वास्तविक सामग्री' के बारे में भी।"

15. इस निर्णय को निंगावा बनाम बैरप्पा [(1968) 2 एस. सी. आर. 797 में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था: ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 956] यह देखा गया: (एस. सी. आर. पीपी. 800-01)

"यह अच्छी तरह से साबित है कि धोखाधड़ी से प्रेरित या दूषित एक अनुबंध या अन्य लेनदेन अमान्य नहीं है, लेकिन केवल धोखाधड़ी करने वाले पक्ष के विकल्प पर अमान्य है। जब तक इससे बचा नहीं जाता, तब तक लेन-देन वैध होता है, ताकि धोखाधड़ी की सूचना के बिना तीसरे पक्ष इस बीच उस मामले में अधिकार और हित प्राप्त कर सकें जिसे वे धोखाधड़ी करने वाले पक्ष के खिलाफ लागू कर सकते हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह एक अमान्य लेनदेन होगा।लेकिन स्थिति को अलग माना गया था यदि धोखाधड़ी या गलत निरूपण दस्तावेज़ के चरित्र से संबंधित था।इस अदालत ने कहा:(एस. सी. आर. पी. 801)

“ कानूनी स्थिति अलग होगी यदि न केवल दस्तावेज़ की सामग्री के बारे में धोखाधड़ी से गलत निरूपण किया जाता है, बल्कि

उसके चरित्र के बारे में।अधिकारी दस्तावेज़ के चरित्र के रूप में धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण और उसकी सामग्री के रूप में धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं।पहले वाले के संदर्भ में, यह माना गया है कि लेन-देन अमान्य है, जबकि बाद वाले के मामले में, यह केवल अमान्य है।”

(जोर दिया गया) हालांकि सॉन्डर्स बनाम एंग्लिया बिलिंग सोसाइटी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स [1971 एसी 1004:(1970) 3 सभी ई. आर. 961] ने कानून की समीक्षा की और माना कि सिद्धांत की आवश्यक विशेषताएँ, जैसा कि बायल्स, जे. द्वारा फोस्टर बनाम मैकिनन [चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, 25 वीं संस्करण में व्यक्त की गई हैं।,पी. 341], सही कहा गया था। हालाँकि, लॉर्ड रीड ने कहा:(पी. 1005 पर एसी हेडनोट)

“कम से कम दस्तावेज़ के सामान्य प्रभाव को ठीक करने के लिए परेशानी उठाए बिना हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गैर-तथ्य की याचिका उपलब्ध नहीं हो सकती थी।न ही यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकता है जिसकी गलती वास्तव में दस्तावेज़ के कानूनी प्रभाव के रूप में एक गलती थी।उन्होंने जो हस्ताक्षर किए और जो उन्होंने सोचा था कि वह हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनके बीच एक कट्टरपंथी या मौलिक अंतर होना चाहिए।”

19. न केवल बिस्मिल्लाह (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित गैर-तथ्य की याचिका के तत्व वर्तमान मामले में मौजूद हैं, बल्कि तीन मापदंड भी हैं जो सॉन्डर्स (उपर्युक्त) से निकाले जा सकते हैं जो वर्तमान मामले में भी मौजूद थे।एक सफल याचिका के लिए उपरोक्त परीक्षण

इस तथ्य की आवश्यकता नहीं है कि:

ए. गैर-तथ्य का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उन व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जो बिना किसी गलती के, अंधेपन, निरक्षरता या किसी अन्य विकलांगता के कारण विशेष दस्तावेज़ के उद्देश्य की कोई समझ रखने में असमर्थ हैं।अक्षमता वह होनी चाहिए जिसमें सलाह के लिए दूसरों पर निर्भरता की आवश्यकता हो कि वे क्या हस्ताक्षर कर रहे हैं।जैसा कि लॉर्ड पियर्सन ने उचित रूप से कहा था:

361

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 362

“मेरी राय में, गैर-तथ्य की याचिका एक ऐसे व्यक्ति की राहत के लिए एक उचित मामले में उपलब्ध होनी चाहिए जो स्थायी या अस्थायी कारणों से (अंधेपन या निरक्षरता तक सीमित नहीं) हस्ताक्षर किए जाने वाले विलेख या अन्य दस्तावेज़ को पढ़ने और पर्याप्त रूप से समझने दोनों में सक्षम नहीं है।” “पर्याप्त रूप से समझदारी” से मेरा मतलब है कि कम से कम वास्तविक दस्तावेज़ और दस्तावेज़ के बीच एक मौलिक अंतर का पता लगाने के बिंदु तक समझना, जैसा कि हस्ताक्षरकर्ता ने माना था।”

बी. “हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए जा रहे दस्तावेज़ की सामग्री की प्रकृति के बारे में एक मौलिक गलती की होगी”, जिसमें इसके व्यावहारिक प्रभाव भी शामिल हैं। लॉर्ड विल बफ़ोर ने इस पहलू को संक्षेप में रखा है:

“मेरी राय में, किसी दस्तावेज़ को (अमान्य के विपरीत) केवल तभी अमान्य माना जाना चाहिए जब उसके लिए सहमति के तत्व की पूरी तरह से कमी हो, यानी अधिक ठोस रूप से, जब वह लेन-देन जो दस्तावेज़ प्रभावी होने का इरादा रखता है, अनिवार्य रूप से उद्देश्यित लेन-देन से सार या प्रकार में भिन्न हो।

ग. दस्तावेज़ हस्ताक्षर किए जाने के इरादे से मौलिक रूप से अलग होना चाहिए। जैसा कि लॉर्ड रीड ने फैसले में टिप्पणी की:

“मुझे लगता है कि उन्होंने जो हस्ताक्षर किए और जो उन्होंने सोचा था कि वह हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनके बीच एक मौलिक अंतर होना चाहिए-या कोई “मौलिक” या “गंभीर” या “बहुत महत्वपूर्ण” शब्दों का उपयोग कर सकता है।” लेकिन एक कट्टरपंथी अंतर क्या है, यह सभी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।”

इन तीनों मानदंडों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है और तत्काल मामले में भी बनाया गया है।

20. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने उचित विचार करते हुए कहा था कि वादी अपीलार्थी ने पावर ऑफ अटॉर्नी को अमान्य घोषित करने के साथ-साथ बिक्री विलेखों को रद्द करने के लिए भी कोई राहत नहीं मांगी थी। कानून अच्छी तरह से तय है कि जहां यह आरोप लगाया जाता है कि बिक्री का दस्तावेज़ अमान्य है, तो किसी भी रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह के दस्तावेज़ को कानून के तहत नजरअंदाज किया जा सकता है। बिक्री विलेख को रद्द करना केवल तभी आवश्यक होगा जब इसे कथित रूप से रद्द किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

तथ्यावर्तमान मामले में धोखाधड़ी का गलत प्रतिनिधित्व न केवल दस्तावेज़ की सामग्री के लिए था, बल्कि दस्तावेज़ के चरित्र के लिए भी था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा तय कानूनी स्थिति के विपरीत दिए गए तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है।

21. वाद के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि गैर-तथ्य की याचिका को स्पष्ट और सख्त शब्दों में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। वादी इसे साबित करने में सक्षम थे या नहीं, यह एक अलग सवाल होगा, लेकिन यह तथ्य कि इसका अनुरोध किया गया था, स्पष्ट से अधिक है। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह आदेश दर्ज करने में सही नहीं था कि वादी ने याचिका के संबंध में अभिवचन नहीं किया था

यह तथ्य नहीं है।

22. इस स्तर पर ही उपरोक्त पहलू पर तय की गई कानूनी स्थिति का उल्लेख करना उचित होगा। इस न्यायालय ने भगवती प्रसाद बनाम चंद्रमौल 14 के मामले में बहुत उपयुक्त रूप से कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालयों के लिए विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या पक्षकारों को पता था कि विचाराधीन मामला शामिल था और क्या उन्होंने इसके बारे में साक्ष्य का नेतृत्व किया था। हम उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 10 को स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं:

“10. लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों के इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करते समय, दूसरे सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है कि रूप के विचार सार के वैध विचारों पर हावी नहीं हो सकते हैं। यदि कोई याचिका विशिष्ट रूप से नहीं की जाती है और फिर भी यह निहितार्थ द्वारा एक मुद्दे द्वारा कवर किया जाता है, और पक्षकारों को पता था कि उक्त याचिका मुकदमे में शामिल थी, तो केवल यह तथ्य कि याचिका को अभिवचनों में स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, आवश्यक रूप से एक पक्ष को उस पर भरोसा करने से वंचित नहीं करेगा यदि यह सबूत द्वारा संतोषजनक रूप से साबित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि राहत पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन जहां मुकदमों में दोनों पक्षों के स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को छुआ जाता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से या यहां तक कि अस्पष्ट रूप से, और उनके बारे में सबूत दिए गए हैं, तो यह तर्क कि एक विशेष मामले को अभिवचनों में स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, विशुद्ध रूप से औपचारिक और तकनीकी होगा और हर मामले में सफल नहीं हो सकता है। इस तरह की आपत्ति से निपटने में न्यायालय को जिस पर विचार करना है वह है: क्या पक्षकारों को पता था कि विचाराधीन मामला मुकदमे में शामिल था, और क्या उन्होंने इसके बारे में सबूत पेश किए? यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को पता नहीं था कि मामला मुकदमे में मुद्दा था

14 ए. आई. आर 1966 एस. सी. 735 363

रामथल और ओआरएस. वी. विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 364

और उनमें से एक को इसके संबंध में साक्ष्य देने का कोई अवसर नहीं मिला है, यह निस्संदेह एक अलग मामला होगा। एक पक्ष को ऐसे मामले पर भरोसा करने की अनुमति देना जिसके संबंध में दूसरे पक्ष ने साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया है और जिसे साक्ष्य का नेतृत्व करने का कोई अवसर नहीं मिला है, पूर्वाग्रह के विचार पेश करेगा, और एक पक्ष के साथ न्याय करने में, न्यायालय दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता है।”

23. उक्त अनुपात का पालन इस न्यायालय ने 2008 में बच्चाज नाहर बनाम नीलिमा मंडल और अन्य 15 के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया है। इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिवचनों और मुद्दों का उद्देश्य और उद्देश्य बताया। उक्त रिपोर्ट का पैरा 12 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“12. अभिवचनों और मुद्दों का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वादियों पर सभी मुद्दों के साथ मुकदमा चलाया जाए और मामलों को विस्तार से रोका जाए या मुकदमे के दौरान आधार को स्थानांतरित किया जाए। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के प्रति पूरी तरह से सचेत है जो उठाए जाने या विचार किए जाने की संभावना है ताकि उन्हें अदालत के समक्ष विचार के लिए मुद्दों के लिए उपयुक्त प्रासंगिक साक्ष्य रखने का अवसर मिल सके। इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिवचन दोनों पक्षों को दूसरे के मामले की सूचना देने के लिए हैं ताकि इसे पूरा किया जा सके, अदालतों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाया जा सके कि वास्तव में पक्षों के बीच क्या मुद्दा है, और पाठ्यक्रम से किसी भी विचलन को रोकने के लिए जो विशेष कारणों पर मुकदमेबाजी होनी चाहिए।”

24. विचारण न्यायालय द्वारा बनाए गए मुद्दों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि गैर-तथ्य की याचिका पर कोई मुद्दा विचारण न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

25. निचली अदालत ने निम्नलिखित चार मुद्दों को तैयार किया था:

“((i) क्या वादी मुकदमे की संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं? ((ii) क्या वादी मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में हैं और उसका आनंद ले रहे हैं?

((ग) क्या वादी उस डिक्री के हकदार हैं जिसके लिए अनुरोध किया गया है? ((iv) वादी किस राहत के हकदार हैं?”

15 (2008) 17 एस. सी. सी. 491

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

26. पहले दो मुद्दों में गैर-तथ्य के मुद्दे को इसके एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा, जब वादी ने पूर्ण मालिक होने का दावा किया है, जिससे न केवल पावर ऑफ अटॉर्नी की शुद्धता से इनकार किया जाता है, बल्कि अटॉर्नी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा अपने पिता और भाई के पक्ष में बिक्री विलेख का निष्पादन भी किया जाता है। अन्यथा भी एक बार जब अभिवचनों के संबंध में साक्ष्य पेश किया जाता है, तो मुद्दों को तैयार न करना घातक साबित नहीं हो सकता था ताकि मुकदमे को खारिज किया जा सके। वादी संख्या 1, जिसने गवाह बॉक्स में प्रवेश किया था, ने शिकायत के अनुसार अपनी दलीलों का पूरा समर्थन किया था। प्रथम अपीलिय न्यायालय उसी पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा या, दूसरे शब्दों में, दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और साथ ही रिकॉर्ड पर दिए गए साक्ष्य पर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की सामग्री वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच समझ के अनुसार नहीं थी।

27. प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण, अटॉर्नी भी प्रतिवादी के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेगा और वादी के अभिवचन के पक्ष में एक निष्कर्ष निकालेगा। प्रतिवादी संख्या 2, जिस तारीख को पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत हुआ, उसने बाजार मूल्य के बारे में क्या कहना है, दिशानिर्देश मूल्य से बहुत कम अनुमानित मूल्य पर अपने पिता और भाई के पक्ष में विचाराधीन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए आगे बढ़ा। कथित रूप से बाजार मूल्य संबंधित समय पर 3 लाख रुपये से अधिक होगा। दिशानिर्देश मूल्य Rs.22,500/- होने का अनुमान लगाया गया था जबकि हस्तांतरण Rs.12,000/- के रूप में दिखाए गए विचार के लिए किया गया था। प्रतिवादी अपने इस आचरण की व्याख्या करने में विफल रहा कि वह उसी दिन अपने पिता और भाई को संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए इतनी जल्दबाजी में था। कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क में अवज्ञा को भी मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि दस्तावेज़ को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया गया था और नौ से ग्यारह वर्षों के बाद ही निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद विलेख जारी किए गए थे। जाहिरा तौर पर, प्रतिवादी मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे और यदि वे हार जाते हैं, तो वे स्टाम्प शुल्क पर कोई और राशि निवेश या खर्च नहीं करना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने तब तक भुगतान नहीं करने का फैसला किया जब तक कि लगभग निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज नहीं कर दिया।

28. पावर ऑफ अटॉर्नी ने प्रतिवादी संख्या 2 को अधिकार नहीं दिया। वादी ने यह दावा करना जारी रखा कि वे कब्जे में थे जबकि प्रतिवादियों ने बिक्री विलेख के अनुसार कब्जे में होने का दावा किया।

ए 365

रामथल और ओआरएस. वी.विधिक उत्तराधिकारी एस. के माध्यम से के. राजमणि (मृत)।
AND ANDRI [विक्रम नाथ, जे.] 366

इस आशय का निर्णय भी आया है कि वादी को Rs.12,000/- का भुगतान किया गया था, जिसे वादी ने अस्वीकार कर दिया है। सवाल यह होगा कि क्या प्रतिफल उस संपत्ति के लिए उचित और पर्याप्त था जिसे अटॉर्नी धारक द्वारा हस्तांतरित किया गया था।

29. प्रतिफल का भुगतान बैंक खाते में या चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि नकद में किया गया है, इसलिए, क्या यह वास्तव में भुगतान किया गया था या नहीं, यह वादी या प्रतिवादियों द्वारा मौखिक बयानों में से किसी एक की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। उनके आचरण पर विचार करते हुए प्रतिवादियों के बयान को वादी की तुलना में इसकी वास्तविकता के संदर्भ में कम आधार पर रखा जाएगा। वादी द्वारा हस्ताक्षरित इस तरह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य (रसीद या ऐसी कोई चीज) नहीं है कि उसे कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, अधिकार को वैध रूप से प्रतिवादी को हस्तांतरित नहीं कहा जा सकता है और वैध अधिकार अभी भी वादी के पास रहेगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य, मौखिक और दस्तावेजी दोनों की सराहना और विश्लेषण किया था, ताकि यह तथ्य दर्ज किया जा सके कि गैर-तथ्य की याचिका साबित हुई थी।

30. प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों द्वारा जिस मामले कानून पर भरोसा किया गया है, वह मूल रूप से इस प्रस्ताव के लिए है कि एक पंजीकृत दस्तावेज को न केवल उसके निष्पादन के लिए बल्कि उसकी सामग्री के लिए भी सही माना जाए। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, एक बार जब प्रथम अपीलीय न्यायालय, अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना और विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गैर-तथ्य की याचिका साबित हो गई थी, तो उक्त निर्णय, तथ्य का अंत होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। पावर ऑफ अटॉर्नी, अमान्य पाए जाने के बाद, इसके अनुसार की गई किसी भी आगे की कार्रवाई को भी वैध नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, प्रतिवादी प्रत्यर्थीगणों द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उनके लिए कोई सहायक नहीं हैं।

31. उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तथ्य के शुद्ध तथ्यों को बाधित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और वह भी गलत मूल्यांकन और अभिवचनों को पढ़ने पर। किसी ऐसे मुद्दे को तैयार न करना, जो अन्यथा एक व्यापक मुद्दे में शामिल है और जिसके लिए पर्याप्त दलील और सबूत थे, उस आधार पर मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता था।

32. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थीगण का मुकदमा तय किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

33. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

34. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान